१

ISSN 2349 - 7521
RNI No. MPHIN/2004/14249

मासिक

अक्षर वार्ता

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

वर्ष-15 अंक-08 , मई - 2019
Vol - XV Issue No VIII May 2019
Impact Factor - 2.891

Email : aksharwartajournal@gmail.com

प्रधान संपादक - प्रो.शैलेन्द्रकुमार शर्मा
shailendrasharma1966@gmail.com

संपादक- डॉ.मोहन बैरागी
drmohan128@gmail.com

संपादक मण्डल डॉ.जगदीशचन्द्र शर्मा (उज्जैन),
प्रो.राजश्री शर्मा, डॉ. शशि रंजन 'अकेला' (आरजीपीवी,भोपाल)
सहयोगी सम्पादक- डॉ.मोहसिन खान (महाराष्ट्र),
सह सम्पादक- डॉ.भेरुलाल मालवीय, डॉ. अंजली उपाध्याय
डॉ.पराक्रम सिंह, डॉ.रूपाली सारये,डॉ. डॉ. विदुषी शर्मा,डॉ. मोनिका देवी
प्रबंध संपादक- कृष्णदास बैरागी

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध-पत्र 2500-5000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। o. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कृतिदेव 010 (Kruti Dev 010) या यूनिकोड मंगल फोंट में टाइप करवाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। o. अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाइम्स न्यू रोमन (Times New Roman) एरियल फोंट (Arial) में टाइप करवाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। शोध-पत्र की सॉफ्टकॉपी अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध-पत्र मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। o. Please Follow- APA/MLA Style for formatting अक्षरवार्ता का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 650/- छः सौ पचास रूपये एवं पंजीयन शुल्क रूपये एक हजार पांच सौ का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है।

बैंक विवरण निम्नानुसार है- बैंक -

Corporation Bank,
Account Holder- Aksharwarta
Current Accont NO. 510101003522430
IFSC- CORP0000762,
Branch- Rishi Nagar,Ujjain,MP,India

भुगतान की मूल रसीद,शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है।

Email: aksharwartajournal@gmail.com
संपादकीय कार्यालय का पता- संपादक अक्षर वार्ता
43,क्षीर सागर,द्रविड मार्ग,उज्जैन,म.प्र. 456006,भारत
फोन :- 0734 2550150 मोबा :-8989547427

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

9

अनुक्रम

» यथार्थ के धरातल पर मानवीय गरिमा के लिए संघर्षरत नारी और चन्द्रकान्ता की कहानियाँ
पवन कुमार रावत 06

» पंडित सुंदरलाल शर्मा और केयूर के साहित्य में शिल्प
नम्रता पाण्डेय
निर्देशक- डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति 09

» कहानीकार तेजेन्द्र शर्मा : 'कब्र का मुनाफा' के विशेष संदर्भ में
डॉ. रम्या जी एस नायर 12

» राजकमल चौधरी की हिन्दी रचनाओं में विवाहित स्त्रियों की स्थिति
कुमारी कांता 14

» स्त्री- अभिव्यक्ति को उजागर करती उषा प्रियंवदा की कहानियाँ
डॉ. रीता कुमारी 16

» सुषम वेदी के उपन्यासों में नारी अस्तित्व का संकट
डॉ. जयश्री एस टी 20

» मनमोहन सहगल के उपन्यास 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' में सांस्कृतिक मूल्य
मंजु वाला 22

» वीणा एवं मानसी काव्य की विवेचना
विकांत भास्कर 25

» 21वीं सदी के संस्मरणों में यथार्थ बोध
रेशमा तेजियोत 27

» संजीव की कहानियों में चिंतन के विविध आयाम
पार्वती कुमारी 29

» नवगीत की परंपरा और शंभूनाथ सिंह की कविताएँ
प्रियंका सिंह 33

» तीसरी कसम : लोक और प्रेम
उमेश चन्द्र यादव 36

» कुलवंती उपन्यास में जाति और समाज की अभिव्यक्ति
राज बहादुर यादव 40

» भारत में सूर्योपासना और तीरभुक्ति से प्राप्त कतिपय सूर्य प्रतिमाएं
डॉ. सुशान्त कुमार 43

» शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत-रूस रक्षा संबंध (विशेष संदर्भ : वर्ष 1991 ई. से 2005 ई. तक)
विजय सिंह 47

» धमतरी जिले के ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण
कमल नारायण, शोध निर्देशक- डॉ. प्रमोद यादव 50

» छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद राजनैतिक व प्रशासनिक विकास में अंर्तसंबंध
अजय कुमार
शोध निर्देशक डॉ. श्रीमती अल्का मेश्राम ✓
सह निर्देशक डॉ. श्रीमती वेदवती मंडावी 53

» रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान व्यवहार पर विकास बनाम भ्रष्टाचार
छतर सिंह ठहरे, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी 57

» उज्जैन संभाग की कृषि उपज मंडियों के विकास एवं प्रबंध में मण्डी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय की भूमिका
रामकन्या देवड़ा 61

» अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास में म.प्र. शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन
अम्बाराम सिसोदिया 65

» छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन
डॉ. विजय कुमार साहू, डॉ. भूपेन्द्र कुमार 69

» छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में शासन की योजनाओं का विश्लेषण
✓डॉ. प्रदीप जामुलकर, डॉ. भूपेन्द्र कुमार 72

» शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से बालोद जिले के विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का एक राजनीतिक विश्लेषण
रामकृष्ण साहू, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी
डॉ. श्रीमती अल्का मेश्राम ✓ 75

» लोकतंत्र एवं निर्वाचन सुधार
डॉ. प्रदीप जामुलकर, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी ✓ 78

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

अक्षर वार्ता
ISSN 2349-7521
Vol - XV, Issue - VIII, May - 2019
"AKSHARWARTA" Monthly International Referred Journal

धमतरी जिले के ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण

कमल नारायण, शोध निर्देशक - डॉ. प्रमोद यादव

शोधार्थी तथा सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, एस. आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, छ.ग.

प्रस्तावना:- हमारा देश भारत 200 वर्ष अंग्रेजो का गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की स्थिति विश्व में अत्यंत पिछडे देश की थी। उस समय हमारा देश भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, अंधविश्वास, स्वास्थ्य सेवाओ का अभाव, बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओ से ग्रसित था। आजादी के बाद सन 1951 में भारत मे विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनायी गयी। इन योजनाओ में भारत के ग्रामीण विकास को भी स्थान दिया गया। तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाए बन चुकी है। अभी वर्तमान मे 2012 - 17 तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना गतिमान है।

हमारे देश भारत की लगभग तीन चौथाई आबादी गांवो मे निवास करती है और राष्ट्र तभी समर्थ एवं सम्पन्न होगा जब भारत के सभी ग्रामवासी पिछड़ेपन और गरीबी से मुक्त हो। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे तीव्र तथा स्थायी विकास लाने के लिए कटिबद्ध है जिसे 16 अक्टूबर 1999 को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराते हुए कहा था- भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँच सके।

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी अनेक योजनाए कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इन योजनाओ का उद्देश्य गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन तथा तीव्र सामाजिक, आर्थिक विकास करना है। तदनुसार समाज के उपेक्षित लोगों पर केन्द्रित बहुआयामी नीति के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे चतुर्दिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण बेघर लोगो को घर तथा सभी ग्रामो को ग्रामीण सडको से जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

भारतीय संविधान के नौवें परिच्छेद के अनुसार समस्त ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायतो की स्थापना आवश्यक है। संवैधानिक पंचायतो की स्थापना 73वें संशोधन के बाद 1993 से प्रारंभ हुई है।इसके पूर्व ग्रामीण भारत मे पंचायतों का इतिहास बहुत लम्बा रहा है,जिसका ब्रिटिश शासनकाल मे परिवर्तित रूप से विकास हुआ तथा 1947 के पश्चात् स्वतंत्र भारत मे पंचायती राज संस्थाओं के नाम से विकास यात्रा 1959 मे प्रारंभ हुई।

भारतीय संविधान द्वारा पंचायतो की स्थापना, ग्राम मध्यस्थ व जिला स्तर पर करने का प्रावधान किया गया जहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक है अथवा कृषि से संबंधित कार्यों से जीवन यापन करती है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या की जीवन शैली, संस्कृति व परम्पराए कई हजार वर्ष पुरानी है तथा उनमे राजनीति का व्यवस्थित स्वरूप नगण्य है। प्राचीन भारत के शासकों से लेकर मुगल शासको तक भारतीय शासन व्यवस्था बडे शहरो मे, दुर्गो व राजप्रसादो मे सिमटी रही तथा अधिकांश ग्रामीण निवासी राज के क्रियाकलापो से अछूते ही रहे, जैसा कि कुछ अंग्रेज प्रशासको ने 19वी शताब्दी मे अपने संस्मरणो, प्रशासनिक प्रतिवेदनो व दस्तावेजो मे विवेचन किया था। संविधान की धारा 243 के अंतर्गत आज यह सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की संस्थागत व्यवस्था की राजनीति मे समाहित हो गई है।

पंचायती राज वह व्यवस्था है जो लोकतंत्र को सामान्यजन के घर के दरवाजे तक पहुंचाने का माध्यम है। ग्रामीण विकास को गतिमान बनाने एवं लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम पंचायती राज को माना जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना है। छत्तीसगढ का क्षेत्र पहले ग्रामीण बहुल क्षेत्र था, अभी वह ग्रामीण बहुल क्षेत्र ही है। आज हम छत्तीसगढ के विकास की बात करते है तब हमे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि की बात न कर हमे गांवो के विकास की बात करनी चाहिए। धमतरी जिला मूलतः ग्रामीण कृषि प्रधान जिला है। इस क्षेत्र मे कृषि और वनो पर आधारित गांव फैले हुए है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गांवो का विकास ही धमतरी जिले का वास्तविक विकास है। ग्रामीण विकास ही छत्तीसगढ का विकास है।

ग्रामीण विकास निम्नलिखित अवधारणाओ का समावेश है -

1. ग्रामीण क्षेत्रो मे बुनियादी अवसंरचना सुविधाओ का प्रावधान, पीने के पानी के साथ स्कूलो का संचालन, स्वास्थ्य सुविधाए, सडक, विद्युतीकरण आदि।
2. ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि उत्पादकता मे सुधार।
3. सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओ का प्रावधान।
4. ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढाने के साथ ग्रामीण उद्योग को बढावा देने के लिए योजनाए लागू करना।
5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व परिवारो को स्व-सहायता समूह के माध्यम से क्रेडिट और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

जिला प्रशासन:- भारत मे क्षेत्रीय प्रशासन की मूल इकाई जिला होती है। जिला अपने आप मे सम्पूर्ण प्रशासनिक संस्था है। ऐतिहासिक विरासत एवं बडे-बडे राज्यो से उत्पन्न प्रशासनिक आवश्यकताओ के कारण सारे देश के भूखण्ड को प्रशासनिक रूप से सक्षम इन छोटी-छोटी इकाईयो मे बांटा गया है। इस समय भारत मे 600 से लगभग जिले है जो जनता के प्रशासनिक मामलो मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

खेडा द्वारा उद्धृत जिले/का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रशासनिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिए निश्चित किया गया एक भूखण्ड। इस तरह से जिला

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

9

प्रशासन का अर्थ हुआ एक विशेष क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबन्ध करना। दूसरे शब्दों में जिला प्रशासन राज्य प्रशासन का वह भाग है जो एक जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर कार्य करता है। चूंकि जिला एक ऐसी अत्यधिक सक्षम भौगोलिक इकाई है जहां सार्वजनिक प्रशासन के समस्त उपकरण केन्द्रित किए जा सकते हैं इसलिए जिला प्रशासन सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में सर्वतोमुखी कार्य करता है। भारत में राज्य सरकारे ही प्रशासनिक सुविधा को सम्मुख रखते हुए जिलो का निर्माण करती है।

अतः जिला प्रशासन सरकार की वह सम्पूर्ण कार्यवाही कही जा सकती है जो निश्चित क्षेत्र मे की जाती है । जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला माना जाता है।

जिला प्रशासन का कार्यः-जिला प्रशासन जिसका मुखिया जिलाधीश होता है निम्नलिखित कार्य करती है-

1. कानून एवं व्यवस्था का अनुरक्षण।
2. भू-राजस्व की उगाही।
3. कार्यपालिका सबंधी कार्य।
4. विकास कार्य।
5. स्थानीय निकायो से सम्बद्ध कार्य।
6. विविध कार्य।

प्रस्तावित शोध प्रबंध मे छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका का राजनैतिक विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिले का संक्षिप्त परिचय:- धमतरी जिले की स्थापना 6 जुलाई 1998 को हुआ तथा इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4081.93 वर्ग किलोमीटर है । धमतरी जिला 200-2°-30' से 210-1°-32° अक्षाश तथा 810-23°-17° से 820-10°-35° देशाश के मध्य स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1372.5 मिली लीटर होता है। अधिकतम तापमान मई माह में 44 सेन्टीग्रेट न्यूनतम तापमान 6.6 सेन्टीग्रेट रहता है। धमतरी जिला को रायपुर, कांकेर, बालोद, गरियाबंद जिले की सीमाएँ स्पर्श करती है। यह दो लोकसभा क्षेत्र कांकेर व महासमुंद तथा तीन विधानसभा क्षेत्र सिहावा (56), कुरूद (57), धमतरी (58) मे बटा हुआ है। धमतरी जिले में चार विकास खण्ड धमतरी, कुरूद, नगरी, मगरलोड, 352 ग्राम पंचायत, 637 आबाद गाँव, 96 वन ग्राम है। यहाँ केवल एक नगर निगम धमतरी है। नगर पालिका एक भी नहीं है। नगर पंचायतो की संख्या 5 है। 2011 की जनगणना के अनुसार धमतरी जिले की कुल जनसंख्या 799781 है जिसमे 397897 पुरूष तथा 401884 महिला है। 58581 अनुसूचित जाति के तथा 207633 अनुसूचित जनजाति के लोग है। यहाँ की साक्षरता 78.36 प्रतिशत है। 87.78 प्रतिशत पुरूष और 69.08 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। गोंड, कंवर, हल्बा, कमार यहाँ की प्रमुख जनजाति है तथा हिन्दी और छत्तीसगढ़ी बोली प्रचलित है। 58849 हेक्टेयर मे रबी फसल, 133362 हेक्टेयर मे खरीफ की फसल व 13602 हेक्टेयर मे जायद की फसल लिया जाता है। प्रमुख फसल धान है। 103864 हेक्टेयर (निरा क्षेत्रफल) सिंचित क्षेत्र है।

प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मे भोपालराव पवार शासकीय पालिटेक्निक कॉलेज - रूद्री, धमतरी, बी. जी. कॉलेज धमतरी, शासकीय महाविद्यालय, नगरी, कुरूद, भखारा, मगरलोड तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं मे धमतरी, कुरूद, मगरलोड प्रमुख है। जिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, नगरी मे स्थित है।

यहाँ का प्रमुख खनिज रेत, मुरूम, गिट्टी, पत्थर तथा प्रमुख वनोपज तेंदूपत्ता, सालबीज, लाख, हर्रा है। धमतरी जिले में 100 से अधिक राईस मिले, लाख उद्योग, वनौषधि प्रसंस्करण दुगली, फार्मास्युटिकल उद्योग, ईशा पॉवर प्लांट बंजारी, कुरूद में स्थित है।

अध्ययन विषय का प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्वः- 6 जुलाई 1998 को धमतरी जिले का गठन हुआ तथा 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का 76.76 प्रतिशत जनसंख्या गांवो मे निवास करती है तथा राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य मे ग्रामीण विकास की गति को जानना आवश्यक है तथा जिला प्रशासन की इसमे क्या भूमिका है? इसका राजनीतिक विश्लेषण आवश्यक है ताकि यह जाना जा सके कि ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका पर राजनीति का कितना प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण से निम्नलिखित बाते निकलकर सामने आ सकती है -

1. ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका का ज्ञान होगा।
2. ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका किस हद तक राजनीति से प्रभावित होती है की जानकारी होगी।
3. ग्रामीण विकास के लिए नीतियां बनाने मे सहायता मिलेगी।

उपरोक्त बिन्दु प्रस्तावित शोध का प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्व को स्पष्ट करते है।

शोध कार्य का पुनरावलोकनः-

1. देवेन्द्र कुमार (2014) ने रोल आफवालन्टरी आर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इम्पावरमेंट : ए कम्परेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी आफ सलेक्टेड एन. जी. ओस मे (जे. एन. यू., नई दिल्ली) मे स्वय सेवकों का ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक सशक्तिकरण मे भूमिका का अध्ययन किया है । यह विभिन्न एन.जी.ओ. का तुलनात्मक अध्ययन है।
2. राजिन्दर सिंग बख्शी (2010) ने रूरल डेवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी एन इंटरेक्शन स्टडी आफ रूरल एलाइट एंड ब्युरोक्रेट्स ट्वाड्स डेवलपमेंट (पंजाब विश्वविद्यालय) मे ग्रामीण विकास और नौकरशाही के बीच अंतर्संबंध तथा ग्रामीण अभिजन और नौकरशाह के बीच विकास का अध्ययन किया है । इसमे यह बताया गया है कि ग्रामीण विकास नौकरशाही और ग्रामीण अभिजन से किस प्रकार प्रभावित होती है।
3. जीशान वारसी (2016) ने द रोल आफब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया : ए केस स्टडी आफ उत्तरप्रदेश (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) मे विकास प्रशासन मे नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन किया गया है। जिसमे इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार विकास की नीतिया नौकरशाही के ऊपर आश्रित रहती है।

अध्ययन का उद्देश्यः-प्रस्तावित शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण, धमतरी जिले के संदर्भ मे करना है।

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार की जिले मे संचालित योजनाओ के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. जिला प्रशासन का ग्रामीण विकास मे क्या भूमिका रहती है।
3. क्या जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण जनता अपनी समस्याओ का स्वयं हल कर पाते है?
4. क्या ग्रामीण विकास मे जिला प्रशासन की भूमिका पर राजनीति का प्रभाव

Seth R.C.S Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.)

पड़ा है ?

शोध की संभावित परिकल्पना :-शोध की एक पूर्व कल्पना होती है और उसी के माध्यम से एक शोधकर्ता आगे कार्य करता है मेरे द्वारा चयनित इस शोध रूपरेखा में मेरी उपकल्पना है जिला प्रशासन धमतरी द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों तथा विकास में उसकी भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन कर प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर निष्पादन हेतु क्या-क्या प्रयास किए जा सकते है ।

प्रस्तुत शोध की रूपरेखा के अंतर्गत परिकल्पना को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है :-

1. धमतरी जिला के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जिला प्रशासन का सम्पूर्ण लाभ नही मिल पा रहा है ।
2. जिला के ग्रामीण विकास मे अपना योगदान देने के लिए जिला प्रशासन को कई राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है ।
3. जिला प्रशासन राज्य के विकास मे अपनी भूमिका निभा रहा है, किन्तु कई क्षेत्रों मे यह अब भी कुछ सीमा तक ही प्रभावी है ।
4. जिला प्रशासन के माध्यम से जनता को अपनी समस्याओ के समाधान हेतु बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।
5. जिला प्रशासन से जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है।

अध्ययन की पद्धति :-प्रस्तावित शोध हेतु सामग्री एवं सूचना का संकलन दो प्रकार से किया जाएगा-

(1) प्राथमिक स्त्रोत

(2) द्वितीयक स्त्रोत

प्रस्तुत शोध रूपरेखा को पूर्ण करने मे शोध पद्धति के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो विधियों या स्रोतों का सहयोग प्राप्त किया गया । जो सामाजिक विज्ञान विषयों के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

1) प्राथमिक स्त्रोत:- अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के कारण व निवारण हेतु मौलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार अध्ययन किया जावेगा ।

अ) प्रश्नावली/साक्षात्कार :-दैव निदेशन के द्वारा 300 उत्तरदाताओं का चयन किया जायेगा तथा प्रश्नावली तैयार कर अध्ययन क्षेत्र के चयनित 300 उत्तरदाताओ जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य नागरिकों से अभिमत प्राप्त कर विश्लेषण किया जावेगा।

ब) निर्दशन :- समग्र मे से कुछ इकाईयो को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन द्वारा अध्ययन विषय के बारे मे हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा निदर्शन कितना उत्तम व समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अतः अध्ययन की सफलता के लिए यह आवश्यक है हमारे निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व करने का गुण पर्याप्त आकार, निष्पक्षता, साधनों के अनुरूप, उद्देश्यों के अनुरूप व्यवहारिक तथ्यो पर आधारित तथा स्वतंत्र हो। प्रस्तुत शोध रूपरेखा में तथ्य संकलन हेतु निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जावेगा ।

स) अवलोकन :-घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है । सी.ए. मोजर के अनुसार ठोस अर्थो में अवलोकन मे कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है।

प्रस्तुत शोध परियोजना मे घटना स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की जावेगी।

द) सर्वेक्षण :-शोध क्षेत्र मे भ्रमण कर सूचनादाताओ से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर चारों विकासखण्डों धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी वहां के रहने वाले लोगों, जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्यों, पंच, अधिकारी व कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों से अवलोकन व सर्वेक्षण विधि से तथ्य संकलित किया जावेगा।

ई-विश्लेषण: 300 चयनित उत्तरदाताओ से प्राप्त अभिमत के आधार पर उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जावेगा।

(2) द्वितीयक स्त्रोत:-द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत प्रकाशित प्रलेख, शोध-संस्थाओं के प्रतिवेदन, पत्र-पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक तथा शासन द्वारा समय- समय पर विभिन्न योजनाओ से संबंधित सभी प्रकाशित सामग्री, समाचार पत्र, वेबसाइट, पूर्व की वार्षिक रिपोर्टो का अध्ययन किया जावेगा।

तथ्यों का संकलन :-उपर्युक्त विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत शोध विषय हेतु आवश्यक तथ्यों का संकलन किया जाएगा एवं संकलन करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाएगा।

निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के द्वारा विकास के लिए सकारात्मक प्रयास किया गया तत्पश्चात 2003 के सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश के नये मुखिया डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश की शासन संभाली और प्रदेश का विकास की दिशा मे अग्रसर किया और [illegible] भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न [illegible] विकास को बढ़ावा दिया। सन् 2018 [illegible] सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रदेश के कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक अभिनव योजना की शुरुआत की जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को पुनः सृजित करने की [illegible] को एक सूत्र में बांधने का प्रयास शुरू किया [illegible] योजनाओं को लागू कर जिला विकास के लिए [illegible] है। जिसके लिए जिले में केन्द्र व राज्य सरकार [illegible] जिला प्रशासक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। जिले में [illegible] विकास के लिए यह आवश्यक है कि [illegible] करना है और शासन के विभिन्न योजनाओं [illegible] समान रूप से संचालित करना [illegible]

सुझाव

1) जिले में विकास के लिए विकासखण्ड से लेकर जिले तक निरंतर विकास कार्यों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

2) जिले मे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना।

3) केन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक स्तर पर हर एक हितग्राही तक पहुँचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए।

सदर्भ सूची :-

1. चटर्जी, विश्वबंधु, [illegible] इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायत राज एण्ड [illegible], नई दिल्ली, [illegible], 1966
2. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन 2012-13
3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन 2015
4. कुरूक्षेत्र, अंक-09, जुलाई 2015
5. कुरूक्षेत्र, अंक- 10, अगस्त 2014
6. डे.एस. के. - पंचायती राज इन इंडिया, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 19

Seth R. [illegible] & Commerce DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)